



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 अगस्त, 2009 / 2 भाद्रपद, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 अगस्त, 2009

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ०(5)93 / 2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सनाई, तहसील ठियोग, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	ठियोग	सनाई	24 / 2	0-05-32
			25	0-01-54
			86 / 2	0-08-97
कुल किता-3				0-15-83

शिमला-2, 17 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)99 / 2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महासू, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में चन्द्रनगर-हलाईला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (मीट्रिक) में
शिमला	ठियोग	सनाई	113	0-07-50
			145	0-07-04
			480 / 1	0-04-12
कुल किता-3				0-18-66

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०)एफ०(5)309/2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फायल, तहसील ग्रामीण शिमला, जिला शिमला में फायल दांवटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता के दृष्टिगत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहता, लोक निर्माण विभाग, (द० क्षेत्र) शिमला-3 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) में
शिमला	शिमला ग्रामीण	फायल	306/1	0-01
			309/1	1-03
			312/1	0-16
			कुल किता-3	2-00

शिमला-2, 17 अगस्त, 2009

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ०(5)110/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दर्ईया, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21-ए कि० मी० 49/0 से 66/275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. भूमि का रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र), विन्टर फिल्ड, शिमला-3 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा—बिस्वा) में
सोलन	नालागढ़	रईया	963 / 811	08—16
			812	05—00
			807	00—13
			808	00—03
			964 / 811	14—03
			796	00—14
			950 / 798	02—01
			949 / 798	01—00
			771	01—06
			781	01—14
			769	01—13
			770	01—03
			783	02—00
			785	01—00
			786	01—02
			945 / 795	02—17
			767	01—00
			768	01—12
			799	01—00
			804	01—12
			806	00—14
			761	01—06
			762	07—12
			759	02—09
			760	01—18
			735	00—07
			736	00—07
			737	00—11
			733	01—01
			734	01—19
			732	01—07
			731	02—12
			727	00—14
			729	00—19
			730	00—16
			544	00—05
			548	00—10
			547	00—09
			558	01—11
			559	01—10
			998 / 568	00—03
			570	00—08
			1008 / 572	00—11
			1017 / 679	01—14
			1001 / 571	00—07

574	00-06
575	00-04
1000/571	00-04
1015/679	00-09
573	00-06
1016/679	00-11
999/571	00-3
569	00-12
कुल जोड़ किता-53	85-04

शिमला-2, 17 अगस्त, 2009

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ०(5)121/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव थाना, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21-ए कि० मी० 49/0 से 66/275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. भूमि का रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र), विन्टर फिल्ड, शिमला-3 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) में
सोलन	नालागढ़	थाना	17	02-12
			81	00-01
			19	00-10
			21	01-05
			83	00-02
			14	01-05
			42	00-03
			20	00-10
			15	01-03
			22	01-16
			85	00-09
			87	00-04
			88	00-05
			25	00-06
			86	00-13
			12	03-09

13	02-07
23	00-01
43	00-12
44	01-00
84	00-11
24	00-05
80	00-13
कुल जोड़ किता-23	20-02

शिमला-2, 17 अगस्त, 2009

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ (5)106/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बैहली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21-ए कि० मी० 49/0 से 66/275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. भूमि का रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र), विन्टर फिल्ड, शिमला-3 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
सोलन	नालागढ़	बैहली	401	1-8
			432	4-5
			441	0-12
			394	1-4
			395	2-16
			396	2-9
			397	0-15
			398	0-8
			438	2-2
			436	0-6
			437	1-0
			433	2-14
			442	0-2
			434	2-10
			443	0-3
			399	4-9
			439	3-7

471/440

1-6

470/440

0-6

कुल जोड़ किता-19**32-2**

शिमला-2, 17 अगस्त, 2009

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू (बी)एफ (5)116/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कुण्डलु, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21-ए कि० मी० 49/0 से 66/275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. भूमि का रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र), विन्टर फिल्ड, शिमला-3 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
सोलन	नालागढ़	कुण्डलु	191/2	0-2
			195/17	5-5
			5	3-11
			234/13	1-11
			192/2	0-2
			233/13	1-6
			232/13	1-15
			235/13	1-9
			15	1-12
			8	18-10
			10	10-3
			14	0-13

कुल जोड़ किता-19**45-19**

शिमला-2, 17 अगस्त, 2009

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू (बी)एफ (5)114/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कुन पलेट, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21-ए कि० मी० 49/0 से 66/275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के

निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. भूमि का रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र), विन्टर फिल्ड, शिमला-3 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
सोलन	नालागढ	कुन पलेट	250	1-0
			320 / 229	1-12
			322 / 229	1-12
			246	2-11
			239 / 2	6-7
			446 / 236 / 2	0-3
			242 / 2	9-8
			433 / 235 / 2	7-11
			248	11-5
			289 / 243	5-9
			238 / 2	13-0
			269	36-8
			444 / 418 / 249	0-7
			321 / 229	1-12
			447 / 236	8-19
			445 / 418 / 249	3-3
			417 / 249	3-14
			240 / 2	1-8
			425 / 234 / 2	6-16
कुल जोड़ किता-19			122-05	

शिमला-2, 17-8-2009

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०)एफ०-(5)104/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुनू/582, तहसील पधर, जिला मण्डी में कुनू-बड़ीधार वाया गजौन सड़क के निर्माण करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बिघा में)
मण्डी	पधर	कुन्नु/582	374/288/1	0-10-3
कुल जोड़ किता-1				0-10-3

शिमला-2, 18-8-2009

सं० पी०बी० डब्ल्यू० (बी०)एफ०-(5)239/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव छिपणू, तहसील सदर, जिला मण्डी में मिचुली छिपणू सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा)
मण्डी	सदर	छिपणु	180 / 1	0—13—7
			370 / 181 / 1	0—11—6
			370 / 181 / 2	0—7—18
			369 / 181 / 1	0—8—8
			कुल जोड़ किता—4	2—11—19

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 13 अगस्त, 2009

संख्या: एस0टी0ई0-एफ (4)-2/2008.—जीव अनाशित पदार्थों से निर्मित प्लास्टिक कैंरी बैगज और एक बार में उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की प्रयोज्य वस्तुओं जैसे कप, गिलास व प्लेटों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 15-8-2009 से प्रभावी होने वाली समसंख्यक अधिसूचना तारीख 7-7-2009 को जारी की गई है।

और हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक संगठनों, व्यापार मण्डलों आदि ने प्रतिबन्ध लागू करने से पूर्व, समय सीमा में विस्तार करने के लिए प्रतिवेदन दिए हैं, ताकि वे अपने विद्यमान स्टॉक का निपटारा कर सकें।

अतः पूर्वोक्त तथ्य के दृष्टिगत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 7-7-2009 में आंशिक उपांतरण करते हुए यह अधिसूचित करती हैं कि पॉलीथीन/प्लास्टिक कैंरी बैगज और जीव अनाशित कचरे के बिखराव पर घोषित प्रतिबन्ध 15 अगस्त, 2009 के स्थान पर 2 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी होगा। तथापि, प्रयोज्य कप, प्लेट व गिलास के प्रयोग पर प्रतिबन्ध का प्रवर्तन तत्समय के लिये आस्थगित किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध और हस्तन) नियम, 1998 के अधीन यथा परिभाषित जीव-चिकित्सा संस्थानों को जीव चिकित्सा के प्रबन्धन के लिए प्लास्टिक बैगों का उपयोग करने हेतु अनुज्ञात किया जाता है।

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि तारीख 7-7-2009 की समसंख्यक अधिसूचना में—

- (i) अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ के पैरा-1 में आए शब्दों, "Himachal Pradesh Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995" के स्थान पर "Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995" रखे जाएंगे।
- (ii) पैरा-6 में "दुकानदारों, विक्रेताओं, थोक व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओं, फेरी वालों, रेहड़ी वालों आदि सहित कोई भी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "दुकानदार, विक्रेता, थोक व्यापारी, फुटकर विक्रेता, फेरी वाला, रेहड़ी वाला आदि" शब्द रखे जाएंगे।
- (iii) पैरा-9 के क्रम संख्या '(क)' के अधीन वर्णित विद्यमान शब्द, "एवं प्लास्टिक वस्तुओं का लोप किया जाएगा।
- (iv) पैरा-9 के क्रम संख्या '(ख)' और '(ग)' के अधीन वर्णित शब्द, "प्लास्टिक कचरे" के स्थान पर शब्द "जीव-अनाशित कचरे" शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,
सरोजिनी गंजू ठाकुर,
प्रधान सचिव।

[Authoritative English Text of the Department Notification No. STE-F(4)-2/2008 dated 13-08-2009 as under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th August, 2009

No. STE-F(4)-2/2008.—Whereas Notification of even number dated 07-07-2009 banning use of plastic carry bags and plastic items having one time use such as disposable plastic cups, glasses, plates which are made of non-biodegradable material, has been issued to take effect from 15-8-2009.

And whereas Commercial Organizations, Beopar Mandals etc. in Himachal Pradesh have represented to extend the time period prior to enforcement of the ban to enable them to dispose off their existing stocks.

Now, therefore, in consideration of the aforesaid issue, the Governor, Himachal Pradesh, in partial modification of notification of even number dated 7-7-2009 is pleased to notify that the ban announced on carry bags and littering of nonbiodegradable waste will take effect from 2nd October, 2009 instead of 15th August, 2009. However, the enforcement of ban on disposable cups, plates and glasses is deferred for the time being.

It is further notified that the use of plastic bags for the management of biomedical waste is permitted in Bio- Medical Institutions as defined under the Bio Medical Waste (Management & Handling) Rules, 1998.

It is further notified that in the notification of even number dated 7-7-2009:—

- (i) For the existing words, “Himachal Pradesh Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995” in Para-1, the following words shall be substituted namely:—
“The Himachal Pradesh Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995”.
- (ii) For the words, “person including shopkeepers, vendors, wholesalers, retailers, hawkers, rehriwala etc.” in Para- 6 the following shall be substituted namely:—
“shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, hawker, rehriwala etc.”
- (iii) The existing words, “ and plastic items” mentioned under serial No. ‘(A)’ of Para-9 are deleted.
- (iv) For the existing words, “plastic waste” mentioned under serial No. ‘(B)’ & ‘(C)’ of Para-9 shall be substituted namely:—
“non- biodegradable waste”.

By order,
Sarojini Ganju Thakur,
Pr. Secretary.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

संख्या: एस.एम.एस.-1/2009-10-आर.डी.डी. तारीख शिमला-9 22 अगस्त, 2009

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 32 के साथ पठित धारा 23 की उप-धाराओं (3), (5) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

यदि इन प्रारूप नियमों द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को, उक्त प्रारूप नियमों के बारे में कोई आक्षेप/सुझाव करने हैं, तो वह उन्हें विशेष सचिव (ग्रामीण विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, एस.डी.ए. कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक न0 27 कसुम्पटी, शिमला-171009 को प्रारूप नियमों के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) या सुझाव (वों), यदि कोई है, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

- | | |
|----------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और विस्तार। | <p>1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, हिमाचल प्रदेश (पारदर्शिता, शिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा) नियम, 2009 है।</p> <p>(2) इनका विस्तार, नगरपालिका द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के सिवाए, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।</p> |
| परिभाषाएँ। | <p>2. इन नियमों में जब तक कि कोई बात, विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो:-</p> <p>(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 क 42) अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) "खण्ड कार्यक्रम अधिकारी" से सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी अभिप्रेत है;</p> <p>(ग) "विभाग" से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग अभिप्रेत है;</p> <p>(घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से सम्बद्ध जिला का उपायुक्त अभिप्रेत है;</p> <p>(ङ) "ग्राम रोज़गार सेवक" से अधिसूचना संख्या: एस.एम.एस.-7/2002-आर.डी.डी.-वॉल0-III तारीख 4 अप्रैल,</p> |

संचालित/सुकर करते हैं; और

- (ढ) "राज्य आयुक्त (नरेगा)" से निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय-1

पारदर्शिता

राष्ट्रीय ग्रामीण
रोज़गार गारंटी
अधिनियम की
सामान्य पारदर्शिता।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेज़ों से सम्बन्धित सूचना के पूर्व-सक्रिय प्रकटन के माध्यम से, समस्त सुसंगत सूचना को लोगों तक उपलब्ध करवा के, सम्पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी:—

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व सक्रिय प्रकटन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे;—

- (i) रजिस्ट्रीकरण आवेदनों का संक्षिप्त विवरण;
- (ii) जॉब कार्ड रजिस्टर का संक्षिप्त विवरण;
- (iii) संदाय के लिए देय मस्टर रोलों का संक्षिप्त सार;
- (iv) बेरोज़गारी भत्ता सूचियाँ;
- (v) परिसम्पत्तियों की सूची;
- (vi) सतर्कता और अनुश्रवण समिति के सदस्यों की सूची;
- (vii) माप बुक के संक्षिप्त विवरण;
- (viii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना।

(ख) अन्य स्तरों पर पूर्व सक्रिय प्रकटन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे;—

- (i) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा तैयार किए गए श्रम बजट का संक्षिप्त सार;
- (ii) तकनीकी और प्रशासनिक आकलनों सहित परियोजनाओं के शेल्फ के संक्षिप्त सार;
- (iii) वार्षिक योजना का संक्षिप्त सार;
- (iv) रोज़गार गारंटी निधि लेखा विवरण;
- (v) वार्षिक कार्य योजना तथा बजट प्रस्ताव (ए0डब्ल्यू0पी0बी0) का संक्षिप्त सार;
- (vi) वित्तीय संपरीक्षा रिपोर्टों (तथा की गई कार्रवाई रिपोर्टों) का संक्षिप्त सार;
- (vii) सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट (तथा की गई कार्रवाई रिपोर्टों) का संक्षिप्त सार;
- (viii) उपयोग प्रमाण पत्र;
- (ix) समापन प्रमाण पत्र;

- (x) तकनीकी आकलनों की सूची;
- (xi) शिकायत निवारण रजिस्टर के संक्षिप्त विवरण;
- (xii) संचालित की गई जांचों की सूची;
- (xiii) मूल्यांकन रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण;
- (xiv) निरीक्षण रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण; और
- (xv) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कोई अन्य दस्तावेज़ और सूचना।

पूर्व सक्रिय प्रकटन।

4. (1) ग्राम पंचायत की दशा में, यथास्थिति, ग्राम रोज़गार सेवक और सचिव या पंचायत सहायक, पंचायत समिति या जिला परिषद् की दशा में सचिव, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग की दशा में नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि रजिस्ट्रीकरण के अद्यतन आँकड़े, जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या, कार्य की प्राप्ति की मांग, उन लोगों की सूची जिन्होंने कार्य मांगा हो और उपलब्ध करवाए गए रोज़गार के दिनों की संख्या, उन पात्र व्यक्तियों की सूची जिन्हें अधिनियम के अधीन रोज़गार उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा जिन्हें बेकारी भत्ता संदत्त किया गया था, प्राप्त और व्यय की गई निधियों के ब्यौरे, किए गए संदायों के ब्यौरे, लेखे गए मंजूर संकर्मों की सूची और ग्राम पंचायतों में उनकी प्राथमिकता का क्रम, प्रारम्भ किया गया संकर्म, संकर्म की लागत और उस पर व्यय का ब्यौरा, कार्य की अवधि, सृजित कार्य दिवस, स्थानीय सतर्कता समितियों की रिपोर्टें, तथा मस्टर रोलज़ और सम्पूर्ण किए गए प्रत्येक संकर्म के बिल का समेकन।
- (2) उप नियम (1) में वर्णित दस्तावेज़ों और सूचना का पूर्व सक्रिय प्रकटन निम्न प्रकार से किया जाएगा,—
 - (i) सूचना पटल पर प्रदर्शित करके;
 - (ii) प्रकाशन करके;
 - (iii) ग्राम सभा की सामाजिक संपरीक्षा, फोरम के समक्ष प्रदर्शित करके या को प्रस्तुत करके; और
 - (iv) इंटरनेट पर प्रविष्टि करके।
5. (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम से सम्बन्धित समस्त लेखे और अभिलेख बिना लागत के जनता की छानबीन के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

लेखे और अभिलेख निरीक्षण के लिए रखना।

अध्याय -2

शिकायत निवारण

शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति।

- 6 राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन की बावत, यथास्थिति, खण्ड स्तर पर खण्ड कार्यक्रम अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्राप्त शिकायतों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी होगा।

शिकायत दाखिल करने के लिए प्रक्रिया।

7 (1) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम से सम्बन्धित शिकायतों को प्रस्तुत करने को सुकर बनाने हेतु, एक शिकायत पेटी भी स्थापित की जाएगी।

(2) कोई भी व्यक्ति सम्बद्ध शिकायत निवारण अधिकारी को या तो लिखित में या मौखिक रूप से शिकायत कर सकेगा, जो चाहे लिखित में या मौखिक रूप से प्राप्त शिकायत को, शिकायत रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा तथा समस्त शिकायतें सम्यक् रूप से अभिलेखित की जाएंगी। नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किसी शिकायत का, सम्बद्ध शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा, स्थल सत्यापन और निरीक्षण के माध्यम से जाँच द्वारा, प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर निपटारा किया जाएगा, जो शिकायतकर्ता को उसमें की गई कार्रवाई को लिखित में भी सूचित करेगा।

शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया।

9. (1) यदि शिकायतकर्ता नियम 8 के अधीन की गई कार्रवाई से सहमत नहीं होता है, तो वह सम्बद्ध शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश और कार्यवाहियों के विरुद्ध निम्नलिखित प्राधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकारी की कार्यवाहियों के आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा:-

(i) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी के जिला कार्यक्रम आदेश और कार्यवाहियों के समन्वयक विरुद्ध:

(ii) जिला कार्यक्रम समन्वयक के राज्य आयुक्त आदेश और कार्यवाहियों के (नरेगा)। विरुद्ध:

2) अपील प्राधिकारी, अपील दाखिल करने की तारीख से एक मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

शिकायतों की मानीटरिंग हेतु प्रक्रिया।

10. (1) शिकायत निवारण अधिकारी, प्राप्त की गई शिकायतों और पूर्ववर्ती मास के दौरान उनके निपटारे के सम्बद्ध में मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, सम्बद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक को पश्चात्पूर्व मास के दसवें दिन तक मासिक रिपोर्ट की प्रति भेजेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक, सम्पूर्ण जिला की बावत मासिक विवरण का अनुपालन करेगा और राज्य आयुक्त (नरेगा) को समेकित मासिक रिपोर्ट भेजेगा।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक, उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई मासिक रिपोर्ट की प्रति, राज्य आयुक्त

(नरेगा) को भेजेगा।

- (4) राज्य आयुक्त, (नरेगा), राज्य में शिकायतों के निपटारे को मॉनीटर करने के लिए राज्य स्तर का अधिकारी होगा।

अध्याय—3

सामाजिक संपरीक्षा

**सामाजिक संपरीक्षा
समिति।**

11. (1) ग्राम सभा इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से और उसके तत्पश्चात् पंचायती राज निकायों के प्रत्येक साधारण चुनाव के पश्चात्, अपनी प्रथम सामान्य बैठक में सहमति से, नौ व्यक्तियों से अन्यून, जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी नहीं हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की सामाजिक संपरीक्षा को संचालित करने और सुकर बनाने के लिए, एक सामाजिक संपरीक्षा समिति गठित करेगी:

परन्तु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन गठित सतर्कता समिति के समस्त सदस्यों को सामाजिक संपरीक्षा समिति में सम्मिलित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सामाजिक संपरीक्षा समिति, कम से कम दो कर्मकारों, जिन्होंने उसी ग्राम पंचायत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन चालू पूर्ववर्ती संकर्म में कार्य किया हो, से गठित होगी:

परन्तु यह और कि सामाजिक संपरीक्षा समिति में एक तिहाई से अन्यून सदस्य महिलाएं होंगी।

- (2) यथास्थिति, पंचायत सचिव या पंचायत सहायक, सामाजिक संपरीक्षा समिति का सदस्य सचिव होगा।
- (3) सामाजिक संपरीक्षा समिति, अपनी प्रथम बैठक में, इसके गठन के पश्चात्, इसके सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेगी।
- (4) सामाजिक संपरीक्षा समिति, प्रत्येक वर्ष, कम से कम चार बैठकें करेगी।
- (5) ग्राम पंचायत की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य की बावत, वर्ष की प्रत्येक तिमाही में अधिकतम दो बैठकों के अध्यक्षीन, ऐसी दर पर बैठक फीस संदत्त की जाएगी जैसी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए।

- | | | |
|--|-----|---|
| सामाजिक संपरीक्षा की समय अवधि। | 12. | सामाजिक संपरीक्षा समिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वर्ष में हुई ग्राम सभा की चार बैठकों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की सामाजिक संपरीक्षा का संचालन करेगी। |
| सामाजिक संपरीक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण। | 13 | सामाजिक संपरीक्षा के सदस्यों को, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों और कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। |
| सामाजिक संपरीक्षा के संचालन हेतु कदम। | 14. | <p>(1) ग्राम रोजगार सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक संपरीक्षा समिति की बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, सामाजिक संपरीक्षा समिति को निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना उपलब्ध करवाएगा:—</p> <p>(क) तकनीकी आकलन और मन्जूरी सहित, ग्राम पंचायत में पूर्ण किए गए संकर्म के कार्य वार/स्थान वार ब्यौरे;</p> <p>(ख) संकर्मों के लिए जारी किए गए मस्टर रोलज़ के ब्यौरे;</p> <p>(ग) संकर्मों के निष्पादन के लिए क्रम सामग्री, सम्बन्धित बिल और वॉऊचर सहित उपयोग की गई सामग्री के ब्यौरे;</p> <p>(घ) तकनीकी आकलन और मन्जूरी सहित ग्राम पंचायत में चालू संकर्मों के कार्य वार/स्थान वार ब्यौरे;</p> <p>(ङ) मांगे गए रोजगार की गृहस्थी के तिमाही ब्यौरे, प्रत्येक गृहस्थी को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के दिनों की संख्या और संदत्त की गई मजदूरी के ब्यौरे; और</p> <p>(च) सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज/सूचना।</p> <p>(2) सामाजिक संपरीक्षा समिति, अपनी बैठकों में ग्राम रोजगार सेवक द्वारा इसको उपलब्ध करवाए गए समस्त दस्तावेजों और सूचना को सत्यापित करेगी।</p> <p>(3) सामाजिक संपरीक्षा समिति, इसको प्राप्त दस्तावेजों/सूचना को सत्यापित करने और छानबीन करने के पश्चात् इसके निष्कर्षों और सम्प्रेक्षणों को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे ग्राम सभा के सदस्यों की सूचना के लिए ग्राम सभा की पश्चात्वर्ती बैठक में सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा और उनके विचारों, सुझावों या आक्षेपों को आमन्त्रित किया जाएगा।</p> <p>(4) सामाजिक संपरीक्षा समिति, ग्राम सभा के समक्ष इसको सारांश को पढ़ कर पूर्ववर्ती सामाजिक संपरीक्षा से सम्बन्धित रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई को भी प्रस्तुत</p> |

करेगी। किसी विसम्मति/किन्हीं आक्षेपों को, ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त में सम्बोधित और अभिलिखित किया जाएगा।

- (5) सामाजिक संपरीक्षा सार्वजनिक सहभागिता के लिए खुली होगी। ग्राम सभा और सामाजिक संपरीक्षा समिति के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति/समूह/गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संपरीक्षा की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप के बिना, पर्यवेक्षक के रूप में सामाजिक संपरीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात होगा।

सामाजिक संपरीक्षा के संचालन और सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्ष पर की गई कार्रवाई में खण्ड कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक का उत्तरदायित्व।

15. (1) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, खण्ड स्तर पर, समय पर सामाजिक संपरीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 (2) जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक संपरीक्षा को समय पर किया गया है और उस पर तदनुसार तुरन्त कार्रवाई की गई है।
 (3) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, सामाजिक संपरीक्षा समिति, ग्राम समुदाय के साथ-साथ श्रमिकों सहित समस्त सम्बन्धित लोगों को, ग्राम सभा की बैठक में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, अग्रिम में, लिखित में नोटिस जारी करके सूचित करेगा।
 (4) सम्बद्ध खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम सभा की बैठक में सामाजिक संपरीक्षा करने के एक मास के भीतर, सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्ष पर की गई कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।
 (5) अधिनियम के उल्लंघन से सम्बन्धित समस्त निष्कर्षों को, यदि कोई हैं, शिकायतें समझा जाएगा और निष्कर्ष में किसी विवाद के लिए जांच संचालित की जाएगी।
 (6) निधियों के किसी दुर्विनियोग के लिए गलती करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार दुर्विनियोग की गई निधियों की वसूली उससे की जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification Number SMS-1/2009-10-RDD-Shimla-9, dated the 22nd August, 2009 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

RURAL AND PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 22nd August, 2009

NO. SMS-1/2009-10-RDD.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3), (5) and (6) of section 23 read with section 32 of the National Rural Employment Act, 2005 (Act No. 42

of 2005), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules for carrying out the purposes of the Act *ibid* and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestions(s) to make with regard to the said draft rules, he may send the same to the Special Secretary (Rural Development) to the Government Himachal Pradesh, SDA Complex, Block No. 27, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objections(s) or suggestions(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State government, before finalizing these rules, namely:—

DRAFT RULES

1. Short title extent.—(1) These rules may be called the National Rural Employment Guarantee Scheme, Himachal Pradesh (Transparency, Grievance Redressal and Social Audit) Rules, 2009.

(2) They shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh, except the areas administered by a municipality.

2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

- (a) “Act” means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);
- (b) “Block Programme Officer” means the Block Development Officer;
- (c) “Department” means the Rural Development Department of the Government of Himachal Pradesh;
- (d) “District Programme Coordinator” means the Deputy Commissioner of the concerned district;
- (e) “Gram Sabhas” means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village or villages comprised within the area of a Gram Panchayat;
- (f) “Nodal Officer” means an Officer appointed by the concerned departments of the State Government, which is the implementing agency of any scheme framed under the Act;
- (g) “Record” means and includes—
 - (i) any document, manuscript and file;
 - (ii) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;
 - (iii) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarge or not); and
 - (iv) any other material produced by a computer or any other device;

- (h) “section” means a section of the Act;
- (i) “Secretary” means a person, by whatever name called, appointed under section 133 and sub-section (1) of section 134 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994) to discharge the functions of the Secretary of the Panchayat Samiti and the Zila Parishad concerned;
- (j) “Social Audit Committee” means the persons who conduct/facilitate the Social Audit at Gram Panchayat level; and
- (k) “State Commissioner” means the Director, Rural Development Department, Himachal Pradesh.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined in these rules shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

CHAPTER-1

TRANSPARENCY

3. General transparency of National Rural Employment Guarantee Act.— Complete transparency shall be ensured in the process of administration and decision making, by giving people full access to all relevant information for fulfillment of the objectives of the National Rural Employment Scheme by way of the pro-active disclosure of information relating to the following documents as per sub-rule(2) of rule 4 of these rules:—

- (1) Pro-active disclosure at the Gram Panchayat Level shall include the following,—
 - (i) summary of the Registration Applications;
 - (ii) summary of the Job Card Register;
 - (iii) abstracts of the muster rolls due for payment;
 - (iv) unemployment allowance lists;
 - (v) list of assets;
 - (vi) list of members of the Vigilance and Monitoring Committee;
 - (vii) measurement book summaries;
 - (viii) any other document or information relating to implementation of provisions of the Act.
- (2) Pro-active disclosure at other levels shall include the following,—
 - (i) abstract of the labour budget prepared by the District Programme Co-ordinator;
 - (ii) abstracts of the Shelf of Projects with technical and administrative estimates;
 - (iii) abstract of Annual Plan;

- (iv) employment Guarantee Fund account statement;
- (v) abstract of the Annual Work Plan and Budget Proposal (AWPB);
- (vi) abstract of Financial Audit Reports (and Action Taken Reports);
- (vii) abstract of the Social Audit Report (and Action Taken Reports);
- (viii) utilization Certificate;
- (ix) completion Certificate;
- (x) list of Technical Estimates;
- (xi) summary of the Grievance Redressal Register;
- (xii) list of Enquiries Conducted;
- (xiii) summary of the Evaluation reports;
- (xiv) summary of the Inspection reports; and
- (xv) any other document or information relating to implementation of provisions of the Act.

4. Pro-active disclosure.—(1) It shall be the duty of the Gram Rozgar Sewak in the case of Gram Panchayat, Secretary in the case of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, Nodal Officer in the case of department of the Central Government or the State Government to make public the updated data on registration, number of job cards issued, demand for work received, list of people who have demanded work and the number of days of employment provided, list of eligible persons who could not be provided employment under the Act and were paid unemployment allowance, details of funds received and spent, details of payments made, accounts, list of works sanctioned and their order of priority within the Gram Panchayat, works started, cost of works and details of expenditure on it, duration of work, person-days generated, reports of local vigilance committees, and consolidation of muster rolls and bills of each work completed.

(2) The Pro-active disclosure of documents and information mentioned in in sub-rule (1) shall be made,—

- (i) through displaying on notice board;
- (ii) through publication;
- (iii) through displaying or presenting at the Social Audit forums of the Gram Sabha; and
- (iv) posting on the internet.

5. Accounts and record open to inspection.—(1) All accounts and records relating to NREGS shall be made available for public scrutiny free of cost.

CHAPTER-2

GRIEVANCE REDRESSAL

6. Appointment of Grievance Redressal Officer.—The Block Programme Officer at the Block level and the District Programme Coordinator at the district level, as the case may be, shall be the Grievance Redressal Officer for complaints received in respect of the implementation of NREGS.

7. Procedure for filing complaints.—(1) There shall be maintained a complaint register in the office of the Block Programme Officer and District Programme Coordinator. In addition, a complaint box shall also be installed to facilitate submission of Complaints relating to NREGS.

(2) Any person may make complaint either in writing or orally to the concerned Grievance Redressal Officer who shall get the complaint, whether written or oral, entered in the complaint register and all the complaints shall be acknowledged.

8. Procedure for disposal of complaints.—Any complaint received under sub-rule (1) of rule 7 shall be disposed of within seven working days from the date of receipt by inquiry through spot verification and inspection by the concerned Grievance Redressal Officer who shall also inform the complainant regarding the action taken in writing.

9. Appeal.—(1) In case the complainant is not satisfied with the action taken under rule 8, he may file an appeal against the orders and proceedings of the Grievance Redressal Officer concerned to the following authorities within forty five days from the date of order of proceedings of the Grievance Redressal Officer:—

- | | |
|--|---------------------------------|
| (i) Against the orders and proceedings of the Block Programme Officer. | District Programme Coordinator. |
| (ii) Against the orders and proceedings of the District Programme Coordinator. | State Commissioner (NREGA). |

(2) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within one month from the date of filing of appeal.

10. Procedure for monitoring of complaints.—(1) It shall be the duty of the Grievance Redressal Officer to prepare monthly report in respect of complaints received and disposed of by him during the preceding month.

(2) The Block Programme Officer shall send a copy of monthly report to the concerned District Programme Coordinator by 10th day of subsequent month and the District Programme Coordinator shall compile the monthly statement in respect of whole of the district and send a consolidated monthly report to the State Commissioner (NREGA).

(3) The District Programme Coordinator shall send a copy of monthly report prepared under sub rule (1) to the State Commissioner (NREGA).

(4) The State Commissioner (NREGA) shall be the State Level Officer to monitor the disposal of complaints in the State.

CHAPTER-3

SOCIAL AUDIT

11. Social Audit Committee.—(1) The Gram Sabha, from the date of publication of these rules, and thereafter every general election of the Panchayat in its first general meeting, shall form

by consensus one social audit committee consisting of not less than nine persons, who are not office bearers of the Gram Panchayat, to conduct and facilitate the social audit of NREGS:

Provided that all the members of vigilance committee formed under sub section (4) of section 7 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 shall be included in the social audit committee:

Provided further that the social audit committee shall consist of at least two workers who have worked in current/previous works under NREGS of the same Gram Panchayat:

Provided further that not less than one third members of Social Audit Committee shall be women.

(2) The Panchayat Secretary or Panchayat Sahayak, as the case may be, shall be the member secretary of the social audit committee.

(3) The social audit committee in its first meeting, after its constitution, shall elect amongst its members a Chairperson.

(4) The social audit committee shall hold at least four meetings in each year.

(5) There shall be paid a sitting fee at such rate as notified by the State Government from time to time in respect of member of Gram Panchayat meeting subject to maximum two meetings in each quarter of the year.

12. Time period of social audit.—The social audit committee shall conduct social audit of NREGS in four Gram Sabha meetings required to be held in each year under the provisions of sub section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

13. Training to the members of the Social Audit Committee.—Necessary training shall be imparted to the members of Social Audit Committee as per the orders, memos and executive instructions issued by the State Government from time to time.

14. Steps for conduct of the social audit.—(1) It shall be the duty of the Gram Rozgar Sewak to provide the following documents/information to the social audit committee at least fifteen days before the date of meeting of the social audit committee :—

- (a) Work-wise/place-wise details of works completed in the Gram Panchayat alongwith work-wise technical estimation and sanction;
- (b) Details of muster-rolls issued against these works;
- (c) Details of material purchased for execution of works, material consumed alongwith the related bills/vouchers;
- (d) Work-wise/place-wise details of on-going works in the Gram Panchayat alongwith work-wise technical estimation and sanction;
- (e) Quarter-wise details of households demanded employment, provided employment number of days of employment provided to each household and details of wage payments made to each worker; or
- (f) any other document/information sought by the social audit committee.

(2) The social audit committee in its meeting shall verify all documents and information provided to it by the Gram Rozgar Sewak.

(3) The social audit committee, after verifying and scrutinizing the documents/information received by it, shall prepare a report indicating therein its finding and observations, which shall be read out publicly in subsequent Gram Sabha meeting for the information of the Gram Sabha members and to invite their views, suggestions or objections.

(4) The social audit committee shall also put up action taken report relating to the previous Social Audit before the Gram Sabha by reading out its contents. Any dissent/objections shall be addressed and recorded in the minutes of the Gram Sabha meeting.

(5) The Social Audit shall be open to public participation. Any outside individual person/group/NGO apart from the Gram Sabha and Social Audit Committee shall be allowed to attend the Social Audit as observers without intervening the proceedings of the Social Audit.

(6) Any fund deviations shall follow with an action against the concerned person and fund recovery shall be expedited.

By order,
Sd/-
Secretary.

ब अदालत श्री मनोज कुमार, उप-मण्डल दण्ड अधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेमजीत पुत्र श्री छेरिंग दवा, गांव ओथंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती।

श्री प्रेमजीत पुत्र श्री छेरिंग दवा, गांव ओथंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम पाठशाला प्रमाण-पत्र में प्रेमजीत लिखा गया है जबकि ग्राम पंचायत जाहलमा के परिवार रजिस्टर में रणजीत लिखा गया है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत जाहलमा के परिवार रजिस्टर में अपना नाम प्रेमजीत करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दुरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-9-2009 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज कुमार,
उप-मण्डल दण्ड अधिकारी,
उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, करसोग,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती रामेश्वरी चौहान पत्नी स्व0 श्री सन्त राम चौहान, निवासी वखोहल, डा0 पनंगणा, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में।

यह प्रकण प्रार्थीया ने स्वयं व अधिवक्ता श्री जी0 एस0 चौहान द्वारा उप—मण्डल दण्डाधिकारी करसोग के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो उप मण्डल दण्डाधिकारी करसोग के न्यायालय को स्थानान्तरित हुआ है। प्रार्थीया ने प्रकरण के साथ एक शपथनामा जो दिनांक 22-7-2008 को नोटरी पब्लिक का तस्दीक शुद्धा है, के नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत पनंगणा दिनांक 17-7-2008 जो पंचायत सचिव पनंगणा द्वारा जारी कर्ता है व प्रमाण—पत्र पटवारी हल्का निहरी जो दिनांक 2-6-2009 को जारी किया है जो नायब तहसीलदार निहरी द्वारा 2-6-2009 को प्रतिहस्ताक्षरित हुआ है भी संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में महाल वखौल/200 में रामेश्वरी पुत्री श्री दमोदर के नाम से दर्ज है जबकि व अपना महाल निहरी/19 के आधार पर श्रीमती रामेश्वरी पत्नी श्री सन्त राम के नाम से उपरोक्त महाल में दर्ज करवाना चाहती है जिसकी पुष्टि में उसने उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए व व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल निहरी/19 में स्वर्गीय पति श्री सन्त राम के नाम से दर्ज है अब उसी आधार पर वह महाल वखोल/200 में वह अपने पिता के साथ—साथ अपने पति के नाम से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए व श्रीमती रामेश्वरी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने पर सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया श्रीमती रामेश्वरी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल निहरी/19 के अनुसार महाल वखौल/200 में उसका नाम पिता के साथ—साथ पति के नाम से दर्ज करने बारे किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-9-2009 को इस अदालत में असालतन या वकालतन अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है व कोई एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल वखोल/200 में उसका नाम पिता के साथ पति के नाम से तस्दीक कर दिए जाने के आदेश नियमानुसार प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एस0 एस0 ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एस0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, करसोग,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री तिलक राज उर्फ तावे राम पुत्र श्री शिव राम चौहान, निवासी वालणा, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— राजस्व रिकार्ड के नाम दुरुस्ती करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्री तिलक राज उर्फ तावे राम पुत्र श्री शिव राम, निवासी वालणा ने दस अदसलत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जो प्रार्थी ने दिनांक 27-5-2009 का सत्यापित करवाया है। नकल इन्तकाल नम्बर 14, महाल चलोग/499 जो तस्दीक शुद्धा है, एक पंजीकृत वसीयत नम्बर 4 जो दिनांक जो दिनांक 12-1-2004 का जो उसके पिता शिव राम ने अपने पुत्र के नाम तस्दीक कह है प्रमाण-पत्र सचिव ग्राम पंचायत सेरी बगलो जो दिनांक 20-3-95 को जारी किया गया नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत भनेरा जो पंचायत सचिव ने दिनांक 16-8-2008 को जारी की है व नकल जमाबन्दी महाल चलोग/499 खाता खतौनी नम्बर 9/9 जमाबन्दी वर्ष 2004-05 प्रस्तुत किए हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह व्यक्त किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भनेरा के रिकार्ड में तिलक राज उर्फ तावे राम दर्ज है जो की सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल चलोग/499 में उसका नाम तावे राम है जो कि गलत है व उसने प्रार्थना-पत्र में यह भी व्यक्त किया है कि उसका सही नाम तावे राम है जो कि गलत है जबकि सही नाम तिलक राज उर्फ तावे राम है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए व श्री तिलक राज उप-नाम तावे राम द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने पर सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम राजस्व रिकार्ड के महाल चलोग/499 दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-9-2009 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व प्रार्थी तावे राम का नाम महसल चलोग/499 में तिलक राज उपनाम तावे राम दर्ज करने के आदेश नियमानुसार प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एस0 एस0 ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, रोन्हाट, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री चान्दनू राम पुत्र श्री कालू राम, ग्राम खाड़ी, उप-तहसील रोन्हाट।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती बारे।

श्री चान्दनू राम पुत्र श्री कालू राम, ग्राम खाड़ी, उप-तहसील रोन्हाट ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक दरखास्त गुजारी है कि उसका सही नाम चान्दनू राम है, परन्तु ग्राम पंचायत शंखौली के पंचायती रिकार्ड में उसका नाम चाननू राम दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी इस गलती को दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-9-2009 को प्रातः 10.00 बजे इससे पूर्व अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही कर सचिव ग्राम पंचायत शखौली को दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज सिंह गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती फुलमा देवी पत्नी श्री रण सिंह, ग्राम किणू (पनोग), उप-तहसील रोनहाट।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती बारे।

श्रीमती फुलमा देवी पत्नी श्री रण सिंह, ग्राम किणू (पनोग), ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी अपनी जन्म तिथि 31-12-1966 है परन्तु ग्राम पंचायत पनोग के पंचायती अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 31-12-1999 को 34 वर्ष दजे है कि गलत है। प्रार्थी इस गलती को दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-9-2009 को प्रातः 10.00 बजे इससे पूर्व अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज सिंह गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर, उप-मण्डल दण्डाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री हेम राज पुत्र श्री शिव राम, निवासी ग्राम खरयावण, डा0 अर्की, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

पंचायत अभिलेख में मृत्यु की तिथि दर्ज करने बारे।

श्री हेम राज उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी माता श्रीमती दसोधा पत्नी स्व0 श्री शिव राम, निवासी खरयावण, तहसील अर्की का देहान्त दिनांक 1-4-1993 को उनके घर पर हुआ था लेकिन गलती से उनकी मृत्यु की तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके जिसे अब दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-9-2009 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा मृत्यु की तिथि नियमानुसार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-8-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बलवीर ठाकुर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर, उप-मण्डल दण्डाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री बलदेव राज पुत्र श्री हरि राम, निवासी ग्राम ज्यालंग, परगना पोबर, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

पंचायत अभिलेख में नाम दर्ज करने बारे।

श्री बलदेव राज उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्रों सर्वश्री दीपक कुमार की जन्म तिथि 22-2-2004 व मनीष कुमार की जन्म तिथि 9-10-2007 है। लेकिन किन्हीं कारणों से उनका नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका जिसे अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री बलदेव राज के उपरोक्त पुत्रों के नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख में पंजीकृत करने पर यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असातन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर दिनांक 30-9-2009 को अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले सुनवाई नहीं होगा और नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-7-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बलवीर ठाकुर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

भजन लाल

बनाम

आम जनता

आवेदन—पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भजन लाल पुत्र श्री ईशर दास, वासी बीटन, तहसील हरोली ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र यशपाल का जन्म दिनांक 29-7-2004 को गांव बीटन में हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बीटन के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-9-2009 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत बीटन को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

गणेश चन्द

बनाम

आम जनता

आवेदन—पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गणेश चन्द पुत्र श्री बिहारी लाल, वासी कांगड़, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती शीला देवी की मृत्यु दिनांक 25-8-1992 को गांव कांगड़ में हुई है लेकिन उनकी मृत्यु की तिथि ग्राम पंचायत कांगड़ के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-9-2009 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कांगड़ को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-8-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।